

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....पवित्र कौठारी.....

बनाम जितेंद्र.....

किस्म मुकदमा :- 212 R.T. Act

नंबर/००० वर्ष 20२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8-6-23	<p>पत्रावली पशासन गांवों के संग/महंगाष्ट राहत कैम्प- 2023 कैम्प कोर्ट-सिनौदिया में पैदा हुई वकील पार्थी व पेरौकार सरकार उपास्थित। वकील पार्थी व पेरौकार सरकार की बहस सुनी गयी वकील पार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पार्थी द्वारा दिनांक 13-5-91 को ग्राम सिनौदिया के ख. न. 32 रकबा 10-04 बीघा भूमि जरिये विक्रय-पत्र के हीरा पुत्र रतना जाति खाती नि०-सिनौदिया से बुझ की थी। बुझ दिनांक से पार्थी का कब्जा-का बत चला आ रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम शिव नगर में ख. न. 32 रकबा 1.6503 हेक्टेयर अंकित है। विक्रित भूमि जरिये किरासत मामला-न्तरकरण से अपार्थी सं. 1 से 5 के नाम अंकित हो जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। उक्त वादग्रस्त भूमि पार्थी की खरीदशुदा भूमि है। इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः पार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। पेरौकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अपार्थी सं. 1 से 5 के जम्मा रिकार्ड में दर्ज है एवं प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित उभावित नहीं होता है।</p>	



हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 12 राजस्थान का श्रमिक अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तार तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय आज दिनांक 8-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आम (केम्प-कोर्ट) में सुनाया गया।

08.6.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

